[2017] 7 एस.सी.आर. 194

रंजन सिन्हा एवं अन्य

बनाम

अजय कुमार विश्वकर्मा एवं अन्य

(नागरिक अपील संख्या 8121/2004)

3 जुलाई, 2017

[जगदीश सिंह केहर, मुख्य न्यायाधीश, एन. वी. रमण और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश]

फार्मेसी अधिनियम, 1948:

अधिनियम का उद्देश्य, फार्मासिस्ट की भूमिका - चर्चा की गई - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 ।

धारा 31, 32 पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार पहली रजिस्टर को नवगठित झारखंड राज्य और बिहार राज्य के लिए पहली रजिस्टर माना जाएगा - पहली रजिस्टर को पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार किया गया और पंजीकरण के समय फार्मासिस्टों द्वारा दिए गए निवास स्थान के आधार पर क्षेत्रीय संबंधों के आधार पर विभाजित किया जाएगा - झारखंड राज्य राज्य परिषद का गठन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है - जो फार्मासिस्ट पूर्ववर्ती बिहार राज्य की पहली रजिस्टर में पंजीकृत हैं, और जो अपने निवास स्थान वाले राज्य में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वे धारा 32(2) के अनुसार दूसरे राज्य में पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उन फार्मासिस्टों को जिन्होंने पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार की गई पहली रजिस्टर में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं, झारखंड राज्य में धारा 32(2) के तहत पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करनी होगी और उन्हें शिक्षा विनियम द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 धारा 84, 85 भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 ।

धारा 32 उपरांत रजिस्टर - शिक्षा विनियम लागू होने के बाद, केवल वे व्यक्ति जिनके पास शिक्षा विनियम द्वारा निर्धारित योग्यता है, पंजीकरण के पात्र होंगे - इस प्रकार, धारा 31 में उल्लिखित योग्यता केवल धारा 30 के तहत पहली रजिस्टर तैयार होने तक ही प्रासंगिक होगी - बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000:

धारा 84, 85 - पूर्ववर्ती बिहार में नियुक्त तिथि से पहले सभी लागू कानून झारखंड और बिहार के क्षेत्रों पर लागू माने जाएंगे।

रंजन सिन्हा और एएनआर. बनाम अजय कुमार विश्वकर्मा

जब संसद द्वारा नए राज्य का गठन होता है, तो क्या नवगठित राज्य के क्षेत्रों में पूर्ववर्ती राज्य द्वारा बनाए गए कानून लागू होते रहते हैं - जब संसद द्वारा मौजूदा राज्य का क्षेत्र पुनर्गठित किया जाता है तो प्रभुसत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है - यह केवल कुछ क्षेत्रों को मौजूदा राज्य से नवगठित राज्य में स्थानांतरित करने का समायोजन है - इसलिए, जो भी कानून पुनर्गठित राज्य के क्षेत्रों पर लागू थे, वे नवगठित राज्य के क्षेत्रों पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नया राज्य या तो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन कानूनों को अनुकूलित, संशोधित या निरस्त नहीं करता।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 3: अंतरराष्ट्रीय कानून में लागू 'स्वच्छ पट्टी' का सिद्धांत अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्गठन के समय लागू नहीं होता है। पुनर्गठित राज्य सामान्यतः शून्य से शुरुआत नहीं करते, बल्कि वे पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी होते हैं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. जब 1940 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम बनाया गया, जिसने भारत में बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए, तब फार्मासिस्ट की भूमिका के महत्व को समझा गया। औषधि नियम, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत बनाए गए थे, ने निर्धारित किया कि चिकित्सा व्यवसायी के पर्चे पर तैयार की गई दवाएं केवल फार्मासिस्ट द्वारा ही बेची जा सकती हैं। योग्य फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में, भारत के लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को खतरा था। इसलिए फार्मेसी के पेशे और अभ्यास को विनियमित करने के उद्देश्य से 1947 में फार्मेसी विधेयक संसद में पेश किया गया। इसे चयन समिति को भेजा गया, जिसने सिफारिशें कीं। इन्हें शामिल करते हुए, विधेयक पारित हुआ। उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट करता है कि केवल न्यूनतम पेशेवर शिक्षा वाले व्यक्तियों को ही फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए एक केंद्रीय फार्मेसी परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें फार्मेसी शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने की शक्तियाँ होंगी। इसके अलावा, योग्य फार्मासिस्टों के प्रांतीय रजिस्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव था। अधिनियम लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती बिहार ने पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन किया, जिसने फार्मासिस्टों की पहली रजिस्टर तैयार की और राज्य सरकार ने इसे अधिनियम की धारा 30 (4) के अनुसार प्रकाशित किया। [पैरा 12, 13][208-G-H; 209-A-C]

2. जब अधिनियम पूर्ववर्ती बिहार में पहली बार लागू हुआ, तो फार्मेसी में न तो कोई औपचारिक कोर्स था और न ही केंद्रीय परिषद द्वारा कोई शिक्षा विनियम बनाया गया था। धारा 31 ने पहली रजिस्टर की तैयारी के लिए अस्थायी उपाय के रूप में फार्मासिस्टों के लिए योग्यता निर्धारित की। अधिनियम की धारा 32 बाद के पंजीकरण के लिए योग्यता निर्धारित करती है। धारा 32 (2) के अनुसार, शिक्षा विनियम लागू होने के बाद, केवल वे व्यक्ति जो शिक्षा विनियम द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं, फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज होने के पात्र हैं। [पैरा 18][212-C-D]

3.1 15.11.2000 से झारखंड के गठन के बाद, बिहार पुनर्गठन अधिनियम (BROA) की धारा 3 के कारण, पूर्ववर्ती बिहार के क्षेत्रों को झारखंड में शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप वे क्षेत्र बिहार के क्षेत्र नहीं रहे, लेकिन BROA की धारा 84 और 85 ने 2000 से पहले लागू सभी अधिनियमों को संरक्षित किया और यह प्रावधान किया कि बिहार के पुनर्गठन के प्रावधान (धारा 3 से 6, अध्याय 2, BROA) किसी भी कानून के लागू होने वाले क्षेत्रों

में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कानून में बिहार का कोई क्षेत्रीय संदर्भ उस क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा जो नियुक्ति तिथि से पहले बिहार के मौजूदा क्षेत्र के भीतर था। BROA की धारा 84 में उल्लिखित सभी कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उन्हें उपयुक्त सरकार (केंद्रीय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो) द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, BROA की धारा 2 (f) में 'कानून' की परिभाषा में किसी भी अधिनियम, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य उपकरण शामिल हैं, जो नियुक्ति तिथि से पहले पूरे या किसी भी हिस्से में कानून की शक्ति रखते थे। इसलिए, पूर्ववर्ती बिहार में नियुक्ति तिथि से पहले तुरंत लागू सभी कानून झारखंड और बिहार के क्षेत्रों पर लागू माने जाएंगे और कानूनों की लागू होने के उद्देश्य से ये क्षेत्र पूर्ववर्ती बिहार राज्य के क्षेत्र माने जाएंगे। [पैरा 19, 20][212-E-H; 213-A]

3.2 धारा 31 और 32 यह स्पष्ट करती हैं कि पहली रजिस्टर में फार्मासिस्टों का नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित योग्यता शिक्षा विनियम लागू होने के बाद दूसरी रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए निर्धारित योग्यता से अलग है। जब विधायिका ने अधिनियम बनाया, तब शायद ही कोई फार्मेसी कॉलेज थे जो समर्पित फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रदान करते थे। इसे ध्यान में रखते हुए, संसद ने धारा 31 के तहत शिक्षा विनियमों के गठन तक सीमित अवधि के लिए योग्यता निर्धारित की। अधिनियम के लागू होने के बाद, धारा 10 और 11 के कारण केंद्रीय परिषद को फार्मेसी शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिए शिक्षा विनियम बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार, धारा 30 और 31 को केवल उस समय तक प्रभावी और लागू होना था जब तक केंद्रीय परिषद शिक्षा विनियम नहीं बनाती। यही कारण है कि धारा 32 वाक्यांश 'धारा 30 की उपधारा (2) के तहत नियुक्त तिथि के बाद और राज्य में शिक्षा विनियम लागू होने से पहले' के साथ शुरू होती है। ऐसे मामले में, यदि कोई व्यक्ति राज्य में फार्मेसी के पेशे का अभ्यास करता है और राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। धारा 32 की उपधारा (2) के अनुसार, शिक्षा विनियमों के अधिनियमित होने के बाद, किसी व्यक्ति को रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार केवल तभी होगा जब वह शिक्षा विनियमों द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो। इस प्रकार, धारा 31 में उल्लिखित योग्यता केवल धारा 30 के तहत पहली रजिस्टर की तैयारी तक ही प्रासंगिक होगी। [पैरा 21][213- B-E]

3.3 प्रश्न यह है कि क्या पूर्ववर्ती बिहार द्वारा तैयार की गई पहली रजिस्टर नवगठित झारखंड राज्य की पहली रजिस्टर मानी जाएगी। अधिनियम 1948 में भारत में लागू हुआ, जिसमें पूर्ववर्ती बिहार भी शामिल था। धारा 29 (1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अध्याय IV के प्रभावी होते ही फार्मासिस्टों की एक रजिस्टर तैयार करनी होगी, और इस प्रकार तैयार की गई रजिस्टर को पहली रजिस्टर माना जाएगा। धारा 31 उन लोगों के लिए योग्यता निर्धारित करती है जिनका नाम पहली रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पहली रजिस्टर में पंजीकरण के उद्देश्य से, राज्य सरकार एक पंजीकरण न्यायाधिकरण का गठन करेगी और इस प्रकार तैयार की गई पहली रजिस्टर को प्रकाशित करेगी। तैयार और प्रकाशित की गई पहली रजिस्टर बिहार राज्य के सभी फार्मासिस्टों के संबंध में एक स्थायी रजिस्टर होगी। इसे धारा 19 के तहत गठित राज्य परिषद को सौंपा जाएगा। धारा 30 की उपधारा (4) और (5) का पढ़ना यह दिखाएगा कि राज्य सरकार द्वारा अपील सुनने के लिए नियुक्त एक प्राधिकारी पहली रजिस्टर में एक नया नाम दर्ज करने या इसे संशोधित करने के प्रश्न का निर्णय करेगा। यह सुविधा धारा 30 की उपधारा (2) के

तहत नियुक्त तिथि के बाद और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए शिक्षा विनियमों के लागू होने से पहले उपलब्ध है। [पैरा 22, 23][213-F-G; 214-A-C]

4. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित के अनुसार, अधिनियम की धारा 30 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पूर्ववर्ती बिहार के लिए पहली रजिस्टर को विधिवत प्रकाशित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 3, अन्य बातों के साथ, संसद को कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 का प्रभाव यह है कि अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संसद द्वारा बनाया गया कानून पूरक, परिणामस्वरूप और आकस्मिक प्रावधानों को शामिल कर सकता है। जब संसद द्वारा मौजूदा राज्य का क्षेत्र पुनर्गठित किया जाता है तो प्रभुसत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल मौजूदा राज्य से नवगठित राज्य में कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित करके क्षेत्रों का समायोजन है। इसलिए, जो भी कानून पुनर्गठित राज्य के क्षेत्रों पर लागू थे, वे नवगठित राज्य के क्षेत्रों पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नया राज्य या तो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इन कानूनों को अनुकूलित, संशोधित या निरस्त नहीं करता। जब भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत राज्य का पुनर्गठन करने वाला कानून बनाया गया, संसद ने इस स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए प्रावधान शामिल किए। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1960 का बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 का उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम और 2014 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रावधान शामिल थे, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मौजूदा राज्य के कानून सभी स्थानांतरित क्षेत्रों पर लागू होंगे। [पैरा 24-26][214-C-D, E-H; 215-A; 216-A-B]

5. बीआरओए की धारा 84 में दो कानूनी काल्पनिकताएँ शामिल हैं, पहली यह है कि बिहार के पुनर्गठन से पहले और पुनर्गठन के बाद बिहार राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की लागू करने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, बिहार द्वारा बनाया गया कानून पूर्ववर्ती बिहार राज्य के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा, जिसमें पुनर्गठन के बाद झारखंड राज्य के क्षेत्र भी शामिल हैं। दूसरी काल्पनिकता यह है कि जब तक झारखंड इसे संशोधन या अन्यथा नहीं प्रदान करता, किसी भी कानून में बिहार का क्षेत्रीय संदर्भ पुनर्गठन से पहले के बिहार के सभी क्षेत्रों का मतलब होगा। उदाहरण के लिए, यदि बिहार ने एक ऐसा कानून बनाया था जो पूरे बिहार पर लागू होता, तो यह बिहार और झारखंड दोनों पर लागू होगा जब तक इसे नए राज्य द्वारा संशोधित नहीं किया जाता। जिस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था, उसके क्षेत्र भी उन क्षेत्रों को शामिल करेंगे जो झारखंड में शामिल थे। धारा 85 एक सक्षम प्रावधान है जो दोनों राज्यों को नए राज्य के लिए लागू कानून में संशोधन और अनुकूलन करने का अधिकार देता है। [पैरा 29][218-A-C]

6. पुनर्गठन से पहले बिहार में प्रकाशित पहली रजिस्टर को झारखंड के नवगठित राज्य की पहली रजिस्टर माना जाएगा, जिसमें वे फार्मासिस्ट शामिल होंगे जो झारखंड को हस्तांतरित किए गए क्षेत्रों के निवासी थे। जब एक राज्य, जो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा है, पुनर्गठित होता है, तो कानून के आवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित तीन चीजें होंगी: (i) मौजूदा राज्य (मूल राज्य) जिसने विभिन्न कानून बनाए, जारी रहेगा; (ii) कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित करके बनाया गया नया राज्य कानूनों के लागू करने के उद्देश्य से मूल राज्य के क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा; और (iii) मूल राज्य द्वारा बनाए गए वे कानून नए राज्य पर तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें नए राज्य के संबंध में

सक्षम विधायिका द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाता और परिभाषा खंड में परिभाषित 'कानून' वह कानून होगा जो मौजूदा राज्य में लागू था और नवगठित राज्य में लागू होगा। [पैरा 34, 35][223-A-C]

7.1 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद नए राज्यों का निर्माण, संशोधन, मिलाना, क्षेत्र को कम या बढ़ा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू 'स्वच्छ स्लेट' के सिद्धांत को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्गठन के समय लागू नहीं किया जा सकता। पुनर्गठित राज्य आमतौर पर टैबुला रासा के रूप में शुरू नहीं होते हैं, बल्कि वे पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी होते हैं। बीआरओए के तहत, झारखंड बिहार से निकाला गया और दो अलग-अलग राज्यों का गठन 15.11.2000 को हुआ। यदि विभाजन के दिन लागू कानून समाप्त हो जाते, तो नवगठित राज्य को कानूनों के बिना राज्य बना देने के कारण एक अराजक स्थिति उत्पन्न होती। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, बीआरओए की धारा 84 और 85 जैसे प्रावधानों को जारी रखने और साथ ही राज्यों को आदेश जारी करके आवश्यक संशोधन और अनुकूलन करने का अधिकार देने के लिए अधिनियमित किया गया है। 'कानून' में 'कानूनी बल रखने वाले अन्य साधन' शामिल हैं। 'शामिल है' शब्द के उपयोग को देखते हुए, बीआरओए की धारा 2 (f) के तहत 'कानून' की परिभाषा को व्यापक रूप से व्याख्या किया जाना चाहिए। बिहार द्वारा तैयार की गई पहली रजिस्टर का धारा 2(f) के तहत कानूनी बल है। [पैरा 36, 37][223-D-H]

7.2 इस दृष्टिकोण से, जब पंजीकरण न्यायाधिकरण द्वारा तैयार की गई फार्मासिस्टों की पहली रजिस्टर बिहार सरकार द्वारा धारा 30 के उपधारा (4) के तहत प्रकाशित की गई थी, तो यह अंतिम है और किसी भी समावेशन के माध्यम से संशोधन को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षा विनियमों के निर्माण तक किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 31 द्वारा निर्धारित योग्यता पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, शिक्षा विनियमों के लागू होने के बाद और साथ ही बाद के पंजीकरण के समय, सरकार को शिक्षा विनियमों का पालन करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा विनियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखता, वह फार्मेसी रजिस्टर में प्रवेश पाने के योग्य नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से, जब बिहार राज्य को फिर से पहली रजिस्टर तैयार करने से रोका गया है, तो झारखंड राज्य को भी कानूनी रूप से पहली रजिस्टर तैयार करने का अधिकार नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सही निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने बीआरओए की धारा 84 के प्रभाव को पहली रजिस्टर के संदर्भ में पूरी तरह से नहीं माना, हालांकि यह निष्कर्ष निकाला कि पहली रजिस्टर को फिर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य के लिए पहली रजिस्टर पहले से तैयार की गई बिहार की पहली रजिस्टर है जिसमें वे सभी फार्मासिस्ट शामिल हैं जो अब झारखंड राज्य में रह रहे हो सकते हैं। जहां तक बीआरओए का सवाल है, हालांकि अधिनियम को बीआरओए की धारा 84 और 85 के तहत अपनाया गया था, ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से, धारा 84 लागू करते हुए, पूर्ववर्ती बिहार द्वारा तैयार की गई पहली रजिस्टर झारखंड के लिए पहली रजिस्टर मानी जाएगी और जारी रहेगी। इससे झारखंड को धारा 32 और 32A और 32B के अनुसार बाद के पंजीकरण को लेने से नहीं रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में झारखंड के संबंधित प्राधिकारी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर संशोधित शिक्षा विनियमों का पालन करना होगा। बीआरओए की धारा 86, इस न्यायालय को धारा 84 और 85 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कानून की व्याख्या करने का स्पष्ट अधिकार देती है। बीआरओए के सभी प्रावधानों पर विचार करने के बाद, पूर्ववर्ती बिहार राज्य के फार्मासिस्टों की पहली रजिस्टर में सभी फार्मासिस्ट जिनके आवासीय पते, जैसा कि उसमें दिखाया गया है, झारखंड राज्य के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें झारखंड की पहली रजिस्टर का हिस्सा माना जाएगा। रजिस्टर में

रंजन सिन्हा और एएनआर. बनाम अजय कुमार विश्वकर्मा

अतिरिक्त नामों का भविष्य में समावेश फार्मेसी अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। झारखंड राज्य निकट भविष्य में, यदि पहले से नहीं किया गया हो, एक राज्य परिषद का गठन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। परिणामस्वरूप, झारखंड राज्य सरकार के 12.11.2001 के पंजीकरण न्यायाधिकरण के गठन की अधिसूचना को धारा 30 के तहत और धारा 31 के तहत आवेदन मांगने के लिए विज्ञापन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया है। [पैरा 38, 39, 41 और 42][224-A-E; 225-G-H; 226-A-C]

पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह **(1976) 3 SCC 242 : [1976] 2 SCR 115;** *शेर सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त (योजना), पंजाब* **(1987) 2 SCC 439 : [1987] 2 SCR 691;** *दयानंद बनाम भारत संघ* **(1996) 7 SCC 47: [1995] 3 Suppl. SCR 533;** *वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची बनाम स्वर्णा रेखा कोक्स और कोल्स (प्राइवेट) लिमिटेड* **(2004) 6 SCC 689: [2004] 2 Suppl. SCR 633 पर भरोसा किया गया।**

मामला कानून संदर्भ

[1976] 2 SCR 115	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 30**
[1987] 2 SCR 691	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 31**
[1995] 3 Suppl. SCR 533	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 32**
[2004] 2 Suppl. SCR 633	**पर भरोसा किया गया**	**पैरा 33**

सिविल अपीलेटिव क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8121 of 2004।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के 18.06.2003 के आदेश और निर्णय से संबंधित W. P. (PIL) संख्या 1429 of 2002।

मनिंदर सिंह, एएसजी, ए. मरियार्तुपम, अजित कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट्स, श्रीमती अरुणा माथुर, यूसुफ खान, अवनीश अर्पुतम, श्रीमती अनुराधा अर्पुतम (M/s. अर्पुतम, अरुणा & कंपनी के लिए), श्रीमती बीना गुप्ता, प्रभास बजाज, रोहित राठी, अक्षय अमृतांशु, रतन कुमार चौधरी, ए. पी. मयी, कुमार परिमल, ए. सेल्विन राजा, मिश्रा सौरभ, अंकित कुमार लाल, श्रीमती वंशजा शुक्ला, सी. डी. सिंह, श्रीमती साक्षी कक्कड़, वरिंदर कुमार शर्मा, मोहम्मद शाहिद हुसैन, अशोक माथुर, बी. के. सतीजा, प्रतिनिधि पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय

न. वि. रामना, जज द्वारा दिया गया। 1. इस मामले में **'झारखंड'** राज्य की जटिलताओं और पूर्ववर्ती **'बिहार'** राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के नए बंटवारे वाले राज्य पर लागू होने की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इस सिविल अपील में हमें फार्मेसी अधिनियम, 1948[इसके बाद संक्षिप्तताके लिए **'अधिनियम'**] के धारा 30, 31 और 32 की सीमा और 15.11.2000[इसके बाद संक्षिप्तताके लिए **'BROA'**] के बाद नए राज्य पर उनकी लागू होने की

स्थिति को निर्धारित करना है। जिन प्रश्नों पर विचार करना है, उनमें BROA के विभिन्न प्रावधानों की भी जांच करनी होगी, जिसे हम संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए करेंगे।

2. यह अधिनियम 1948 में भारत में, जिसमें बंटवारा से पहले का बिहार भी शामिल था, लागू हुआ। बिहार राज्य में, फार्मेसी अधिनियम के धारा 30 के तहत 07.02.1955 को राज्य फार्मेसी परिषद की स्थापना की गई और इसके परिणामस्वरूप, फार्मासिस्टों की पहली रजिस्टर तैयार की गई। इस बीच, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा धारा 10 के तहत बनाए गए शिक्षा विनियम 07.02.1958 से लागू हो गए। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विनियमों के लागू होने के बाद, केवल ऐसे व्यक्ति जिनके पास उन विनियमों के अनुसार योग्यताएँ थीं, को फार्मासिस्टों की रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता था।

3. विभाजन के बाद, झारखंड ने 12.11.2001 को अधिनियम के धारा 30 के तहत रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का गठन किया। उक्त ट्रिब्यूनल ने 14.01.2002 को निम्नलिखित अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें झारखंड राज्य में फार्मासिस्टों के पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

हिंदुस्तान

रांची, पटना, दिल्ली और लखनऊ से प्रकाशित

रांची, सोमवार 14 जनवरी 2002

झारखंड सरकार स्वास्थ्य

चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग

(चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान)

प्रेस अधिसूचना

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 40(i) दिनांक 10.01.2002 के अनुसार, **फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 31 के तहत** सभी व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.02.2002 निर्धारित की गई है।

पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क निम्नलिखित हैं:

1. पंजीकरण शुल्क

आवेदन पत्र शुल्क	:₹25/-
प्रोत्साहन शुल्क	:₹25/-
पंजीकरण शुल्क	:₹200/-

2. नवीनीकरण शुल्क

प्रोत्साहन शुल्क	:₹25/-
नवीनीकरण शुल्क	:₹100/-
3. कोई आपत्ति प्रमाण पत्र शुल्क	:₹100/-
4. डुप्लिकेट प्रमाण पत्र शुल्क	:₹275/-
5. देर से आवेदन शुल्क	:₹25 प्रति वर्ष

आवेदन पत्र फार्मेसी संस्थान, रांची के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं और पूरा किया गया फार्म और बैंक ड्राफ्ट उसी स्थान पर जमा किया जा सकता है।

एसडी/- (प्रकाश कुमार)
सरकार के उप सचिव.

P.R. 2278 (स्वास्थ्य 100) 2001-2002

(जोर दिया गया)

4. प्रेस अधिसूचना से स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों के पास अधिनियम की धारा 31 के तहत योग्यताएँ थीं, वे फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के योग्य थे। असंतुष्ट होकर, मान्यता प्राप्त संस्थानों से फार्मेसी में डिप्लोमा धारक और फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत तीन व्यक्तियों ने रिट याचिका संख्या डब्ल्यू.पी. 2002 की संख्या 1429 दायर की, जिसमें 14.01.2002 की प्रेस अधिसूचना को रद्द करने और रांची के रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, जो कि यहाँ प्रतिवादी संख्या 6 है, को यह आदेश देने की प्रार्थना की कि केवल ऐसे व्यक्तियों को फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत किया जाए, जिनकी योग्यताएँ शिक्षा विनियम, 1991 के अनुसार हैं, यानी जिनके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या राज्य परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री है। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क किया कि जब बिहार के पूर्ववर्ती द्वारा धारा 30 के तहत पहली रजिस्टर तैयार की गई, तो झारखंड द्वारा पहली रजिस्टर को दोबारा तैयार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और कि किसी भी आगामी पंजीकरण या रजिस्टर की तैयारी धारा 32 के अनुसार होगी, जिसमें केवल वही व्यक्ति फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने के योग्य होंगे जो शिक्षा विनियमों के अनुसार योग्यताएँ पूरी करते हैं।

5. उच्च न्यायालय के समक्ष, झारखंड ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि नए राज्य के गठन पर उसे धारा 30 के अनुसार पहली रजिस्टर तैयार करने का अधिकार प्राप्त हुआ और इसके लिए एक पंजीकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जो उन सभी को पंजीकृत करे जो धारा 31 के अनुसार योग्यताएँ रखते हैं। राज्य फार्मेसी परिषद ने भी इसी तरह का तर्क प्रस्तुत किया। यह रिकॉर्ड में है कि 14.01.2002 की अधिसूचना के अनुसार प्राप्त 10950 आवेदनों में से एक बड़ी संख्या, यानी 8940 व्यक्तियों के पास फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा नहीं था। लेकिन इनमें से सभी ने धारा 31(d) के आधार पर पंजीकरण की मांग की।

6. झारखंड उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने अधिनियम और BROA की लागू धारा के विस्तृत विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्ववर्ती बिहार के लिए लागू शिक्षा विनियम झारखंड के नए राज्य के लिए भी धारा 84 और 85 के तहत कानून हैं और इसलिए जब तक कोई व्यक्ति शिक्षा विनियमों के अनुसार योग्य नहीं होता, वह पंजीकरण नहीं करा सकता। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

> याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क किया गया कि फार्मेसी अधिनियम बिहार राज्य में लागू हुआ था और इसने अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी शिक्षा विनियमों को अपनाया था, जो अधिनियम के भाग ॥ में था। इसलिए, दोनों अधिनियम और शिक्षा विनियम झारखंड के लिए कानून हैं, जब तक कि शिक्षा विनियम या फार्मेसी अधिनियम में कोई संशोधन, परिवर्तन या रद्दीकरण नहीं होता। यह भी कहा गया कि झारखंड के राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया और जब तक कोई व्यक्ति शिक्षा विनियमों के अनुसार योग्य नहीं होता, वह रजिस्टर में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। हमें इस तर्क में काफी बल लगता है। यह सच है कि झारखंड 15.11.2000 से अस्तित्व में आया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 के अनुसार फार्मेसी अधिनियम और शिक्षा विनियम लागू होते हैं। यदि अधिनियम या शिक्षा विनियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन या रद्दीकरण नहीं होता, तो यह मानना उचित नहीं होगा कि कानून झारखंड राज्य के गठन के साथ समाप्त हो गया। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के लिए एक कानूनरहित राज्य की कल्पना करना संभव नहीं है। यदि प्रतिवादियों का तर्क स्वीकार कर लिया जाए, तो स्थिति यह होगी कि झारखंड राज्य में फार्मेसी या फार्मासिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कोई कानून नहीं है और यह अभी तक बनाया जाना है। दूसरे शब्दों में, जब तक ऐसा कानून नहीं बनाया जाता, एक वैक्यूम रहेगा। ऐसा तर्क, जब तक मजबूर नहीं हो, स्वीकार्य नहीं हो सकता। वर्तमान झारखंड राज्य का क्षेत्र पहले बिहार राज्य का हिस्सा था और इसे अधिनियम और शिक्षा विनियमों के तहत नियंत्रित किया गया था जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 के तहत प्रक्षिप्त और अपनाए गए थे। पुनर्गठन अधिनियम की इस योजना सामान्य सिद्धांत के अनुरूप है कि एक बार किसी क्षेत्र के लिए लागू किया गया कानून उस क्षेत्र पर लागू रहेगा जब तक कि इसे सक्षम विधानमंडल या प्राधिकरण द्वारा रद्द या समाप्त नहीं किया जाता या किसी अन्य कानून द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 10 के तहत प्रक्षिप्त शिक्षा विनियम और धारा 11 के तहत अपनाए गए विनियम उस क्षेत्र पर लागू रहते हैं। भारतीय फार्मेसी काउंसिल द्वारा अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र में अपनाए गए दृष्टिकोण को भी सही माना जाता है।

7. जब झारखंड द्वारा पहली रजिस्टर फिर से तैयार करने के अधिकार पर विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय ने यह कहा कि धारा 30 के अनुसार पहली रजिस्टर तैयार करने की आवश्यकता पर संदेह है और कहा:

> बिहार राज्य के लिए पहले से एक पहली रजिस्टर मौजूद थी, जिसमें झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था, जैसा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित है। जो लोग पहली रजिस्टर में शामिल हैं और जो अपने पेशे को झारखंड के नए क्षेत्रों में निभा रहे हैं, वे झारखंड के नए राज्य में अपने पेशे को जारी रखने का अधिकार रखेंगे। झारखंड के लिए पहली रजिस्टर उन लोगों की होगी जो पहले से ही बिहार के अविभाजित राज्य के लिए तैयार की गई रजिस्टर में शामिल हैं, उनके क्षेत्रीय निष्ठा या उनके पेशे के स्थल के आधार

पर। इसलिए, बिहार राज्य और अधिनियम की धारा 13 के तहत गठित ट्रिब्यूनल द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क के अनुसार, पहली रजिस्टर को पूरी तरह से फिर से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के लिए पहली रजिस्टर पहले से ही बिहार के अविभाजित राज्य के लिए तैयार की गई रजिस्टर है, जिसमें अब झारखंड राज्य के लोग या झारखंड राज्य के क्षेत्रों में अपने पेशे का अभ्यास करने वाले लोग शामिल हैं। केवल योग्य व्यक्तियों के अतिरिक्त नामों की शामिल करने की बात आएगी, यदि वे शिक्षा विनियमों के तहत आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं और फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार। तर्क कि एक राज्य के गठन पर राज्य को धारा 30 के तहत एक पहली रजिस्टर तैयार करनी होगी, धारा 31 के संदर्भ में, इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।

8. उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा अपील की।

<u>विचार के लिए बिंदु</u>

9. इन पृष्ठभूमि तथ्यों और अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित दो बिंदुओं पर विचार उठेंगे:

1. क्या बिहार राज्य द्वारा तैयार की गई पहली रजिस्टर को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 और 85 के अनुसार झारखंड की पहली रजिस्टर माना जाएगा?
2. क्या वे व्यक्ति जो शिक्षा विनियमों के अनुसार कोई योग्यताएं नहीं रखते, झारखंड राज्य द्वारा पंजीकृत होने के योग्य हैं?

<u>प्रस्ताव</u>

10. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. मरियार्पथम ने मुख्य रूप से तर्क किया कि:

a. अधिनियम की धारा पढ़ने पर स्पष्ट है कि हर राज्य/राज्य सरकार के लिए धारा 29 के तहत एक रजिस्टर रखना अनिवार्य है और राज्य परिषद को धारा 29 के तहत आवश्यक रजिस्टर को बनाए रखने का कर्तव्य है।

b. माननीय उच्च न्यायालय ने यह समझने में गलती की है कि हर राज्य को धारा 30 और 31 के तहत एक पहली रजिस्टर अपने तरीके से रखना आवश्यक है, जो कि एक स्पष्ट प्रावधान है। यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो धारा 29, 30 और 31 अप्रचलित और निरर्थक हो जाएंगी।

c. किसी भी स्थिति में, शिक्षा विनियम, जो एक अधीनस्थ विधान है, अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों पर प्रभावी नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रक्रिया निर्धारित की जो अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

11. झारखंड राज्य के लिए श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया कि:

a. धारा 30 के तहत, पहली रजिस्टर को राज्य सरकार द्वारा एक पंजीकरण ट्रिब्यूनल गठित करके तैयार किया जाना चाहिए।

b. पूर्ववर्ती बिहार राज्य में एक रजिस्टर मौजूद था, यह झारखंड राज्य की पहली रजिस्टर तैयार करने की बाध्यता को समाप्त नहीं करता।

c. तथ्य यह कि झारखंड राज्य में शामिल क्षेत्र पहले बिहार का हिस्सा थे, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि झारखंड एक अलग और स्वतंत्र राज्य है और यह एक नया राज्य है, या धारा 30 के तहत इसके अधिकार और कर्तव्य को प्रभावित नहीं करता।

d. पहली रजिस्टर तैयार करने की बाध्यता और झारखंड राज्य के नए राज्य द्वारा ऐसा करने का अधिकार स्पष्ट है और धारा 30 द्वारा सुरक्षित है।

e. ऐसा विचार कि पहली रजिस्टर में धारा 31 के तहत उल्लिखित सभी व्यक्तियों को शामिल करना वांछनीय नहीं है, धारा 30 की व्याख्या में एक कारक या विचार नहीं हो सकता। धारा 30 को उसकी अपनी शर्तों पर व्याख्यायित किया जाना चाहिए और चूंकि भाषा स्पष्ट है, इसे जैसा है वैसा ही लागू किया जाना चाहिए।

f. किसी भी स्थिति में, एक अधीनस्थ विधान जैसे शिक्षा विनियमों को धारा 30 की व्याख्या या अधिकारों, कर्तव्यों और पात्रताओं को कम करने के लिए नहीं आंका जा सकता। धारा 30 और 31 मिलकर पहली रजिस्टर तैयार करने के लिए एक पूर्ण कोड हैं। इस संदर्भ में, शिक्षा विनियमों को व्याख्या के उद्देश्य के लिए शामिल नहीं किया जा सकता, जो केवल धारा 32 अर्थात रजिस्टर में बाद में शामिल करने के लिए प्रासंगिक हैं।

g. बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 और 85 में ऐसी कोई बात नहीं है जो फार्मेसी अधिनियम की धारा 30 और 31 के खिलाफ हो। ये सामान्य प्रावधान हैं जो राज्य के प्रशासन के संदर्भ में लागू होते हैं, जबकि फार्मेसी अधिनियम की धारा 30 और 31 विशेष प्रावधान हैं और फार्मेसी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट/आच्छादित क्षेत्र में, ये प्रावधान प्रबल और लागू होंगे।

<u>बिंदु नंबर 1 और 2</u>

12. हम दोनों बिंदुओं को एक साथ निपटाने का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के लागू होने के बाद, जो भारत में बेची जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता का मानक निर्धारित करता है, एक फार्मासिस्ट की भूमिका के महत्व को महसूस किया गया। ड्रग नियम, जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत बनाए गए थे, ने निर्धारित किया कि जो दवाएं चिकित्सक की पर्ची पर तैयार की जाती हैं, वे केवल एक फार्मासिस्ट द्वारा सीधे बेची जा सकती हैं। एक योग्य फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में, भारत में लोगों के सामान्य स्वास्थ्य को खतरा था। इसलिए, फार्मेसी के पेशे और प्रैक्टिस को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, 1947 में फार्मेसी बिल संसद में पेश किया गया। इसे चयन समिति के पास भेजा गया, जिसने सिफारिशें कीं।

इन सिफारिशों को शामिल करते हुए, बिल पास किया गया। वस्त्र और कारणों का विवरण स्पष्ट करता है कि केवल न्यूनतम पेशेवर शिक्षा मानकों के साथ व्यक्तियों को फार्मेसी पेशे को प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसके लिए एक केंद्रीय फार्मेसी परिषद की स्थापना की प्रस्तावित की गई थी, जिसके पास फार्मेसी शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के अधिकार होंगे। इसके अलावा, प्रांतों में योग्य फार्मासिस्टों के रजिस्टर की स्थापना भी प्रस्तावित की गई थी।

13. अधिनियम के लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती बिहार ने पंजीकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसने फार्मासिस्टों की पहली रजिस्टर को उचित रूप से तैयार किया और राज्य सरकार ने इसे अधिनियम की धारा 30 (4) के अनुसार प्रकाशित किया।

14. अधिनियम के अध्याय। में अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र और प्रारंभ और परिभाषाएँ शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 1 (3) कहती है कि अधिनियम तुरंत लागू होगा, लेकिन अध्याय III, IV, V उन तारीखों से प्रभावी होंगे जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक गजट में अधिसूचित की गई हैं। इसके अलावा, उक्त धारा की उपधारा (3) के तहत प्रावधान कहता है कि यदि 1 नवंबर, 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के कारण भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, तो अध्याय III, IV और V उस राज्य के शेष भाग में ऐसे दिन से प्रभावी होंगे, जैसा कि राज्य सरकार समान रूप से नियुक्त[1] कर सकती है। हालांकि यह तर्क किया गया था कि झारखंड का पुनर्गठन 1956 के बाद प्रभावी हुआ, इसलिए धारा 1 की उपधारा (3) के प्रावधान सीधे झारखंड पर लागू होते हैं, ऐसे तर्क स्पष्ट रूप से गलत हैं क्योंकि प्रावधान की सीधी पढ़ाई से यह स्पष्ट है। प्रावधान का अनुप्रयोग एक बार का उपाय था जो केवल 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए लागू था और इस प्रावधान का अनुप्रयोग 01.11.1956 के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता है।

15. इस चरण में, दो परिभाषाओं का संदर्भ देना उचित होगा जो इस मामले में विवाद के समाधान के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 2 (h) के अनुसार, "रजिस्टर" का मतलब है फार्मासिस्टों का रजिस्टर जो अध्याय IV[2] के तहत तैयार और बनाए रखा जाता है। यह शब्द रजिस्टर का तात्पर्य है कि इसमें पहली रजिस्टर के साथ-साथ बाद की रजिस्टर भी शामिल हैं। आगे, धारा 2 (i) के अनुसार, "पंजीकृत फार्मासिस्ट" का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस राज्य के रजिस्टर में वर्तमान में दर्ज है जिसमें वह वर्तमान में निवास कर रहा है या अपनी फार्मेसी की पेशेवर गतिविधियों या व्यवसाय को चला रहा है।

---

[1]यह प्रावधान अधिनियम 24 के द्वारा जोड़ा गया था, देखें। 2 (व.त. 1-5-1960)

[2]यह परिभाषा अधिनियम 70 के द्वारा जोड़ी गई थी, धारा 2 के लिए, उपधारा (h), (i) और (j) (व.त. 1-9-1976)

16. अधिनियम के अध्याय II[3] में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसके कार्यों का ढांचा शामिल है। अधिनियम की धारा 10 के तहत, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को शिक्षा नियमावली बनाने का अधिकार प्राप्त है, जो फार्मासिस्ट[4] के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा मानक को निर्धारित करती है। इसके अनुसार, फार्मेसी काउंसिल ने 1953 में शिक्षा नियमावली को अधिसूचित किया, जिसे बाद में 1972 के शिक्षा नियमावली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये नियमावली रद्द कर दी गईं और 1981 के शिक्षा नियमावली द्वारा बदल दी गईं। वर्तमान में 1991 के शिक्षा नियमावली लागू हैं (जो 1981 के शिक्षा नियमावली को रद्द कर चुकी हैं), जिन्हें 11.07.1992 को अधिसूचित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि ये शिक्षा नियमावली अब पिछले 50 वर्षों से लागू हैं और देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू की गई हैं। अधिनियम की धारा 11 शिक्षा नियमावली के प्रवर्तन के लिए प्रावधान करती है, जो धारा 10 के तहत बनाई गई हैं।

17. अधिनियम के अध्याय IV में फार्मासिस्टों के लिए योग्यता, *पंजीकरण*, नवीकरण और रजिस्टर से हटाने के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत धारा 29 में राज्य सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि वह राज्य के लिए फार्मासिस्टों का एक रजिस्टर तैयार करे। धारा 30 पहले रजिस्टर के निर्माण के लिए पंजीकरण ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया का विवरण देती है, जिसमें तीन सदस्य होते हैं जिन्हें पहले रजिस्टर को तैयार करने के अधिकार सौंपे जाते हैं। धारा 31 पहले रजिस्टर में पंजीकरण के लिए योग्यता निर्धारित करती है। ये दोनों प्रावधान निम्नलिखित हैं:

> **30. पहले रजिस्टर की तैयारी** - (1) पहले रजिस्टर को तैयार करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार आधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा तीन व्यक्तियों की एक पंजीकरण ट्रिब्यूनल का गठन करेगी और एक रजिस्ट्रार भी नियुक्त करेगी जो पंजीकरण ट्रिब्यूनल के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
>
> (2) राज्य सरकार उसी या समान अधिसूचना द्वारा एक तिथि निर्धारित करेगी, जिस पर या उससे पहले पंजीकरण के लिए आवेदन, जो निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, पंजीकरण ट्रिब्यूनल में किए जाएंगे।
>
> (3) पंजीकरण ट्रिब्यूनल प्राप्त सभी आवेदनों की जांच करेगा और यदि उसे यह संतोष होता है कि आवेदक धारा 31 के तहत पंजीकरण के लिए योग्य है, तो वह आवेदक के नाम को रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देगा।
>
> (4) पहले तैयार किए गए रजिस्टर को फिर राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रकाशित किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट हो, जो प्रकाशित रजिस्टर में व्यक्त या निहित हो, वह उस प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकृत प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है।

---

[3]अधिनियम की धारा 3 से 18 तक शामिल हैं

[4]10. शिक्षा नियमावली - (1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के अधीन, शिक्षा नियमावली बनाने का अधिकार प्राप्त करेगी, जो फार्मासिस्ट के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा मानक निर्धारित करेगी।

(5) रजिस्ट्रार उप-धारा (4) के तहत नियुक्त प्राधिकरण के निर्णयों के अनुसार रजिस्टर में संशोधन करेगा और इसके पश्चात रजिस्टर में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज किया गया है, उन सभी को निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

31. पहले पंजीकरण में प्रवेश के लिए योग्यताएँ -[5] एक व्यक्ति जो अठारह वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है, उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करके पहले पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा यदि वह राज्य में निवास करता है या फार्मेसी का व्यवसाय या पेशा करता है और यदि वह:

(a) फार्मेसी या औषधीय रसायन विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा रखता है या भारतीय विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त बाहरी[6] **[***]** प्राधिकरण द्वारा दी गई निर्धारित योग्यता रखता है,

(b) भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री रखता है जो फार्मेसी या औषधीय रसायन विज्ञान में नहीं है, और उसने अस्पताल या डिस्पेंसरी या ऐसी अन्य जगह पर दवाओं की मिश्रण में तीन साल से कम समय तक कार्य किया है जहां दवाएँ नियमित रूप से चिकित्सकों के पर्चों पर वितरित की जाती हैं,

(c) राज्य सरकार द्वारा सामान्य लोगों या डिस्पेंसर्स के लिए पर्याप्त समझी गई परीक्षा पास की है, या

(d) अस्पताल या डिस्पेंसरी या ऐसी अन्य जगह पर दवाओं की मिश्रण में पांच साल से कम समय तक कार्य किया है जहां दवाएँ नियमित रूप से चिकित्सकों के पर्चों पर वितरित की जाती हैं, पूर्व-निर्धारित तिथि से पहले।

18. जब यह अधिनियम पहले बिहार में लागू किया गया था, तब न तो कोई औपचारिक फार्मेसी पाठ्यक्रम था और न ही केंद्रीय परिषद द्वारा कोई शिक्षा नियमावली बनाई गई थी। धारा 31 ने बिहार के पूर्ववर्ती क्षेत्र में पहले पंजीकरण के लिए फार्मासिस्टों के लिए योग्यताएँ निर्धारित की थीं, एक अस्थायी उपाय के रूप में। अधिनियम की धारा 32 बाद के पंजीकरण के लिए योग्यताएँ निर्धारित करती है। धारा 32 (2) के अनुसार, जब शिक्षा नियमावली लागू की गई, केवल वे व्यक्ति जो शिक्षा नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं, पंजीकरण के लिए पात्र हैं। इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है।

19. 15.11.2000 से झारखंड की स्थापना के बाद, BROA की धारा 3 के कारण, पूर्ववर्ती बिहार के क्षेत्र झारखंड में शामिल कर दिए गए। परिणामस्वरूप, वे शामिल क्षेत्र बिहार के क्षेत्र नहीं रहे, लेकिन BROA की धारा 84 और 85 ने 2000 के तुरंत पहले लागू सभी कानूनों को संरक्षित किया और यह प्रावधान किया कि बिहार के पुनर्गठन के प्रावधान [धारा 3 से 6, अध्याय 2, BROA] क्षेत्रीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करेंगे जिस पर कोई कानून लागू था। इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया कि किसी भी कानून में बिहार का कोई भी क्षेत्रीय संदर्भ, बिहार के मौजूदा क्षेत्रों के भीतर के क्षेत्रों के रूप में समझा जाएगा, नियुक्ति की तारीख से पहले। BROA की धारा 84 में संदर्भित सभी कानून प्रभावी रहेंगे, जब तक कि उन्हें उचित सरकार द्वारा रद्द या संशोधित नहीं किया जाता, यानी, केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा।

---

[5] धारा 9 द्वारा अधिनियम 24, 1959 द्वारा "व्यक्ति को अधिकार होगा" के स्थान पर (1-5-1960 से लागू)

[6] "प्रोविंसिस एट" शब्द को A.O. 1950 द्वारा हटा दिया गया

20. इसके अतिरिक्त, BROA की धारा 2 (f) में 'कानून' की परिभाषा में किसी भी अधिनियम, अध्यादेश, नियमावली, आदेश, उप-नियम, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य औज़ार को शामिल किया गया है, जो नियुक्ति की तारीख से तुरंत पहले, संपूर्ण या किसी भाग में बिहार के पूर्ववर्ती क्षेत्र में कानून की शक्ति रखता था। इसलिए, नियुक्ति की तारीख से तुरंत पहले पूर्ववर्ती बिहार में लागू सभी कानून झारखंड के क्षेत्रों पर लागू माने जाएंगे और बिहार के क्षेत्रों को कानूनों की अनुपालन के लिए पूर्ववर्ती बिहार के क्षेत्रों का हिस्सा माना जाएगा।

21. अधिनियम की ओर वापस लौटते हुए, धारा 31 और 32 के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि पहले पंजीकरण में फार्मासिस्टों के नाम को दर्ज करने के लिए निर्धारित योग्यताएँ, शिक्षा नियमावली के लागू होने के बाद के पंजीकरण के लिए निर्धारित योग्यताओं से अलग हैं। जब विधायिका ने अधिनियम को लागू किया, तब फार्मेसी के लिए समर्पित पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले फार्मेसी कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी। इसे ध्यान में रखते हुए, संसद ने धारा 31 के तहत एक सीमित अवधि के लिए योग्यताएँ निर्धारित कीं, जब तक कि शिक्षा नियमावली का निर्माण नहीं हो जाता। जब अधिनियम लागू हुआ, तब धारा 10 और 11 के कारण केंद्रीय परिषद को शिक्षा नियमावली बनाने की शक्ति प्राप्त हुई, जो फार्मेसी शिक्षा के न्यूनतम मानक को निर्धारित करती है। इसलिए, हमारे विचार में, धारा 30 और 31 केवल तब तक प्रभावी और लागू रहने के लिए थी, जब तक केंद्रीय परिषद शिक्षा नियमावली नहीं बनाती। यही कारण है कि *धारा 32 'उस तारीख के बाद, जिसे धारा 30 की उप-धारा (2) के तहत नियुक्त किया गया है और राज्य में शिक्षा नियमावली लागू होने से पहले' वाक्यांश से शुरू होती है*। ऐसी स्थिति में, एक व्यक्ति को पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा यदि वह राज्य में फार्मेसी का पेशा करता है और राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। धारा 32 की उप-धारा (2) के अनुसार, शिक्षा नियमावली के लागू होने के बाद, एक व्यक्ति को पंजीकरण में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार केवल तब होगा, जब वह शिक्षा नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो। इस प्रकार, धारा 31 में उल्लिखित योग्यताएँ केवल पहले पंजीकरण की तैयारी तक ही प्रासंगिक होंगी। दूसरे शब्दों में, धारा 31 में उल्लिखित योग्यताएँ पंजीकरण के बाद और शिक्षा नियमावली के प्रवर्तन के बाद कोई महत्व नहीं रखती हैं।

22. सवाल यह है कि क्या पूर्ववर्ती बिहार द्वारा तैयार किया गया पहला पंजीकरण झारखंड के नए बने राज्य का पहला पंजीकरण माना जाएगा।

23. अधिनियम भारत में, पूर्ववर्ती बिहार सहित, 1948 में लागू हुआ था। धारा 29 (1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को जैसे ही अध्याय IV प्रभावी होता है, एक फार्मासिस्टों की सूची तैयार करनी होगी, जिसे प्रथम पंजीकरण माना जाएगा। धारा 31 उन योग्यताओं को निर्धारित करती है जिनके तहत व्यक्ति को प्रथम पंजीकरण में दर्ज किया जाएगा। प्रथम पंजीकरण के लिए पंजीकरण त्रैब्यूनल की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और तैयार किया गया प्रथम पंजीकरण प्रकाशित किया जाएगा। तैयार और प्रकाशित पहला पंजीकरण बिहार राज्य में सभी फार्मासिस्टों के लिए एक स्थायी पंजीकरण होगा। इसे धारा 19 के तहत गठित राज्य परिषद के सुपुर्द किया जाएगा। धारा 30 की उप-धारा (4) और (5) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्राधिकृत अधिकारी, जो प्रथम पंजीकरण से संबंधित अपीलों की सुनवाई करेगा, पंजीकरण में नया नाम जोड़ने या संशोधन

करने के प्रश्न को निर्णय देगा। ऐसी सुविधा उप-धारा (2) के तहत नियुक्त तारीख के बाद और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए शिक्षा नियमावली के लागू होने से पहले उपलब्ध है।

24. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पूर्ववर्ती बिहार के लिए प्रथम पंजीकरण धारा 30 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके तैयार किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसे सही ढंग से प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार, बिहार के फार्मासिस्टों का प्रथम पंजीकरण प्रकाशित करने के लिए धारा 30 (4) के तहत एक वैधानिक अधिसूचना जारी की गई थी। 2000 में राज्य के पुनर्गठन के बाद उस प्रकाशित पहले पंजीकरण का क्या प्रभाव है?

25. संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, संसद को किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संसद द्वारा बनाए गए कानून में पूरक, परिणामी और संबद्ध प्रावधान हो सकते हैं। जब संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक नया राज्य बनाया जाता है, तो क्या मौजूदा राज्य द्वारा बनाए गए कानून नए राज्य में शामिल क्षेत्रों पर लागू होते रहते हैं? जब मौजूदा राज्य का क्षेत्र संसद द्वारा पुनर्गठित किया जाता है, तो संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल मौजूदा राज्य के कुछ क्षेत्रों को नए बने राज्य में स्थानांतरित करने का समायोजन है। इसलिए, सभी कानून जो पुनर्गठित राज्य के क्षेत्रों पर लागू होते थे, नए राज्य में स्थानांतरित क्षेत्रों पर लागू होते रहेंगे, जब तक कि नया राज्य उन्हें अपनाए या अपनी क्षमता के अनुसार मौजूदा और लागू कानूनों को संशोधित या रद्द न कर दे।

26. जब भी संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत एक नया राज्य बनाने के लिए कानून बनाया गया, संसद ने ऐसी स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए प्रावधान शामिल किए। 1956[7] का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1960[8] का बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1966[9] का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, "मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000[10], उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000[11], और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014[12] में ऐसी प्रावधान शामिल हैं जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि मौजूदा राज्य में लागू कानून सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे जो नए राज्य के गठन के लिए स्थानांतरित किए गए हैं।"

---

[7] राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, अधिनियम XXXVII 1956।

> **119. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार।** भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां किसी कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।
>
> **120. कानूनों को अपनाने की शक्ति।** किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो किसी भी राज्य में या क्षेत्रीय रूप से बदला गया हो, उपयुक्त सरकार एक साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर

ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

...

[8] बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, अधिनियम XI 1960।

87. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां किसी कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में बंबई राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

88. कानूनों को अपनाने की शक्ति। किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नियुक्ति दिन से पहले बंबई राज्य से महाराष्ट्र या गुजरात में बदल गया हो, उपयुक्त सरकार एक साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

...

[9] पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, अधिनियम XXXI 1966।

88. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां किसी कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में पंजाब राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

89. कानूनों को अपनाने की शक्ति। किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नियुक्ति दिन से पहले पंजाब या हरियाणा राज्य या हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ संघ क्षेत्र में बदल गया हो, उपयुक्त सरकार दो साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

[10] मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, अधिनियम XXVIII 2000।

78. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। इस अधिनियम के भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां किसी कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब

तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

79. कानूनों को अपनाने की शक्ति। किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नियुक्ति दिन से पहले मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य में बदल गया हो, उपयुक्त सरकार दो साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

[11] उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, अधिनियम XXIX 2000।

86. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि धारण की सीमा अधिनियम, 1961 और किसी अन्य कानून के लागू होने में किसी परिवर्तन को प्रभावी किया है, और किसी ऐसे कानून में उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

87. कानूनों को अपनाने की शक्ति। किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नियुक्ति दिन से पहले उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड राज्य में बदल गया हो, उपयुक्त सरकार दो साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

[12] आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014, अधिनियम संख्या VI 2014।

100. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार। भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि धाराओं पर सीमा) अधिनियम, 1973 और किसी अन्य कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

101. कानूनों को अपनाने की शक्ति। किसी भी कानून के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए, जो नियुक्ति दिन से पहले आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य में बदल गया हो, उपयुक्त सरकार दो साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

27. BROA में समान प्रावधान धारा 84 और 85 में निम्नलिखित पाठ हैं:

84. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार - इस अधिनियम के भाग II की प्रावधानों को यह मानने के लिए नहीं समझा जाएगा कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है, जहां किसी कानून का प्रवर्तन नियुक्ति दिन से पहले किया गया था, और किसी ऐसे कानून में बिहार का क्षेत्रीय संदर्भ, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया जाए, उस बिहार के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे।

85. कानूनों को अपनाने की शक्ति - बिहार या झारखंड के संबंध में किसी भी कानून को लागू करने की सुविधाजनकता के लिए, उपयुक्त सरकार दो साल की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा कानून की ऐसे संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है जो आवश्यक या उपयुक्त हों, और फिर हर ऐसा कानून संशोधनों और परिवर्तनों के अनुसार प्रभावी रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदला, रद्द या संशोधित न किया जाए।

व्याख्या - इस धारा में, "उपयुक्त सरकार" का अर्थ है किसी कानून के संबंध में जो संघ सूची में सूचीबद्ध विषय से संबंधित है, केंद्रीय सरकार, और अन्य किसी कानून के संबंध में राज्य में लागू होने के लिए, राज्य सरकार।

28. धारा 84 की सीधी पढ़ाई से निम्नलिखित स्पष्ट होता है। भाग II के प्रावधान, जो पूर्व बिहार के पुनर्गठन से संबंधित हैं, यह नहीं मानते कि उन्होंने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी किया है जहां कोई कानून नियुक्ति दिन से पहले प्रभावी था। किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ को तब तक किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा प्रदान किए बिना, उस राज्य के उन क्षेत्रों को अभिप्रेत किया जाएगा जो नियुक्ति दिन से पहले थे, जब बिहार का पुनर्गठन हुआ था।

29. धारा 84 में दो कानूनी कल्पनाएँ हैं। पहली यह है कि बिहार का पुनर्गठन बिहार द्वारा किए गए कानूनों की प्रासंगिकता को सभी क्षेत्रों पर लागू नहीं करता है जो पुनर्गठन से पहले इसमें शामिल थे और पुनर्गठन के बाद भी। दूसरे शब्दों में, बिहार द्वारा किए गए कानून सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे जो पूर्व बिहार के थे, जिसमें झारखंड के क्षेत्र भी शामिल हैं। दूसरी कल्पना यह है कि जब तक झारखंड इसे संशोधन या अन्य तरीके से प्रदान नहीं करता, किसी भी कानून में बिहार का क्षेत्रीय संदर्भ बिहार के उन सभी क्षेत्रों को अभिप्रेत करेगा जो पुनर्गठन से पहले थे। उदाहरण के लिए, अगर बिहार ने एक कानून बनाया था जो पूरे बिहार पर लागू था, तो यह बिहार और झारखंड पर लागू होगा जब तक कि नए राज्य द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता। इस प्रकार का कानून लागू होने वाले क्षेत्रों में झारखंड के शामिल क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। धारा 85 एक सक्षम प्रावधान है जो दोनों राज्यों को कानून में संशोधन और अनुकूलन करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि वे नए राज्य के लिए लागू हो सकें।

30. अब हम इस न्यायालय के चार निर्णयों पर विचार करेंगे जो उपरोक्त सिद्धांतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। *राज्य पंजाब बनाम बलबीर सिंह*[13] में, प्रतिवादियों ने एक सरकारी आदेश को चुनौती दी जो 28.10.1966 को

जारी किया गया था, जिसमें उन्हें उप-खंड अधिकारी के पद से पुनः नियुक्त किया गया था। इन आदेशों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, यह तर्क करते हुए कि वे सेवा के सदस्य के रूप में स्वचालित रूप से पुष्टि हो गए थे और पंजाब इंजीनियर्स, बिल्डिंग्स और रोड्स ब्रांच (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1942 के तहत और इसलिए उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत पूर्व-स्थापित किए जाने से पहले पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता था। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप अपीलों को भी डिवीजन बेंच द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस न्यायालय के समक्ष केवल यह तर्क था कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 द्वारा आदेश के पुनरावृत्ति का आदेश प्राप्त होने के बाद 1.11.1966 को या उसके बाद, क्योंकि यह प्रशासनिक कानून है, यह कानून नहीं है। यह तर्क न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए अस्वीकार कर दिया:

> यदि उत्तराधिकार राज्यों में कानून की निरंतरता का यह स्थिति हो सकती है, तो कौन से सिद्धांत से कहा जा सकता है कि पूर्व पंजाब राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो गए और नियुक्ति दिन से नया राज्य बनने पर समाप्त हो गए? क्या यह संभव है कि विधानमंडल ने कई प्रावधान किए हों और नए राज्यों की सरकारों द्वारा संशोधित या बदलने तक प्रशासनिक आदेशों के प्रभाव की निरंतरता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया? या यह, कानून और शीलता के दृष्टिकोण से, ऐसा सोचना उचित है कि विधानमंडल ने किसी भी विशेष प्रावधान को बनाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि उन आदेशों की निरंतरता इतनी स्पष्ट थी कि बिना किसी प्रावधान के भी? हमारे विचार में, जब कोई संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होता और यह केवल एक राज्य के क्षेत्रों का समायोजन होता है, तो पूर्व राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश निरंतर प्रभावी रहते हैं और उत्तराधिकारी राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जब तक कि वे संशोधित, बदले या अस्वीकार नहीं किए जाते। अन्य कोई दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य दृष्टिकोण से नए राज्यों के प्रशासन में केवल अराजकता उत्पन्न होगी। हम ऐसा कोई सिद्धांत नहीं पाते हैं जो यह समर्थन करे कि पूर्व राज्य द्वारा किए गए प्रशासनिक आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो गए और नए उत्तराधिकारी राज्यों के अस्तित्व में आने पर अप्रभावी हो गए।"

31. *शेर सिंह बनाम योजना के वित्तीय आयुक्त, पंजाब*[14], मामले में प्रश्न था कि क्या पंजाब सुरक्षा भूमि अधिकार अधिनियम, 1930 के तहत सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति दिन से पहले पारित आदेश नियुक्ति दिन के बाद प्रभावी रहेंगे। अपीलकर्ता का तर्क था कि पंजाब प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गया है और इसलिए उसे हरियाणा राज्य में 50 एकड़ की अतिरिक्त भूमि का अधिकार है। BROA की धारा 88 और हरियाणा कानूनों (राज्य और समवर्ती) आदेश, 1966 का संदर्भ लेते हुए, इस न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

---

[13] (1976) 3 सेक 242

[14] (1987) 2 सेक 439

11. इन दो धाराओं को मिलाकर पढ़ने से स्पष्ट होता है कि 1 नवंबर 1966 से पहले पारित किसी भी आदेश या किए गए किसी भी काम या उत्पन्न किसी भी दायित्व या अर्जित किसी भी अधिकार को आदेश के प्रभावी होने से प्रभावित नहीं किया जाएगा। ये दो धाराएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि संबंधित राज्य सरकारों को 1 नवंबर 1966 से पहले पारित आदेशों को लागू करने का अधिकार होगा, जो अतिरिक्त क्षेत्र की घोषणा करती हैं, और इन आदेशों का सम्मान दोनों राज्यों द्वारा किया जाएगा। तथ्य यह है कि एक विशेष मालिक की भूमि, संयोगवश, दो नई राज्यों में विभाजित हो जाती है, इस तरह के आदेशों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जो 1 नवंबर 1966 से पहले अंतिम हो चुके थे। अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करने से विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी। जिन व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई और जो 1 नवंबर 1966 से पहले अंतिम हो गई, वे दोनों राज्यों में भूमि का दावा करने के पात्र होंगे, जबकि जिनकी याचिकाएँ उस दिन लंबित थीं जब राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यह अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। न ही इसका कोई योजना है। राज्यों का पुनर्गठन एक ऐतिहासिक संयोग था। भूमि मालिक इस संयोग का लाभ नहीं उठा सकते, जो निकाले गए किरायेदारों या पुनर्वास के लिए आवश्यक किरायेदारों को नुकसान पहुंचाएगा।

32. *दयानंद बनाम भारत संघ*[15] एक मामला है जिसमें 1.11.1966 (पूर्व पंजाब राज्य के विभाजन के लिए नियुक्ति दिन) के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (छूट) नियम, 1965 के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार होने की बात की गई है। इस न्यायालय ने *राज्य पंजाब बनाम बलबीर सिंह* के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (छूट) नियम, 1965 के तहत लाभ का विस्तार किया जाना चाहिए और तर्क किया:

4. 1.11.1966 से पहले पंजाब राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश की प्रासंगिकता के संदर्भ में, इस न्यायालय ने *राज्य पंजाब और अन्य बनाम बलबीर सिंह और अन्य* में यह निर्णय लिया कि धारा 88 के तहत, एक पूर्व राज्य द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होते हैं और उत्तराधिकारी राज्य पर प्रभावी और बाध्यकारी रहते हैं जब तक कि उन्हें संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (छूट) नियम, 1965 जो धारा 2(g) के तहत "कानून" की परिभाषा में आते हैं, 1.11.1966 के बाद चंडीगढ़ के संघ क्षेत्र में प्रभावी थे जब तक कि संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा संशोधित, बदले या अस्वीकार नहीं किया जाता। प्रश्न यह है कि क्या संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा 1.11.1966 के बाद 1965 नियमों में कोई संशोधन, बदलाव या अस्वीकार किया गया? यह उल्लेखनीय है कि पंजाब भर्ती नियम, 1982 ने पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (छूट) नियम, 1965 को रद्द कर दिया, लेकिन उसमें बचाव की धारा ने रद्द किए गए नियमों के तहत अर्जित अधिकारों को संरक्षित किया। सभी कर्मचारी, इन मामलों में, 1.11.1966 के बाद लेकिन 1982 नियमों के लागू होने से पहले नियुक्त किए गए थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि 1965 नियम 1.11.1966 के बाद संघ क्षेत्र में प्रभावी थे जब तक कि अस्वीकार या रद्द नहीं किए गए, तो इन मामलों में संबंधित कर्मचारी 1965 नियमों के तहत पात्र होंगे, बशर्ते वे नियमों के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा करें। प्रश्न यह है कि क्या 1965 नियमों को इन कर्मचारियों के लिए संशोधित, अस्वीकार या रद्द किया गया?

...

7. पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन (छूट) नियम, 1965 ने चंडीगढ़ संघ क्षेत्र में 1.11.1966 के बाद भी लागू रहना जारी रखा, जब तक कि संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा संशोधित, बदला या अस्वीकार नहीं किया गया, और ये नियम 1.11.1966 के बाद चंडीगढ़ में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होते रहे जो उन नियमों के लाभ के पात्र थे। यह इस कारण से है कि ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत लागू नहीं होते थे, खासकर क्लास II, III और IV के पदों के लिए। इस दृष्टिकोण को ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया विपरीत दृष्टिकोण सही नहीं ठहराया जा सकता।

33. BROA के धारा 84 और 85 के प्रभाव पर एक बार फिर विचार किया गया था, जब *वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची बनाम स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स (प्राइवेट) लिमिटेड*[16] का मामला आया था। इस मामले में सवाल था कि क्या बिहार के विभाजन और झारखंड के गठन (जिसमें विभाजन से पहले बिहार के क्षेत्र शामिल थे) के बाद औद्योगिक नीति से मिलने वाले लाभ और बिहार वित्त अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना का झारखंड में स्थित उद्योगों को लाभ मिलेगा? इस प्रश्न पर इस न्यायालय ने विचार किया। तर्क दिया गया कि जब तक झारखंड द्वारा समान छूट प्रदान नहीं की जाती, तब तक डीलरों को औद्योगिक नीति के तहत कोई लाभ प्राप्त किए बिना कर का भुगतान करना होगा। इस न्यायालय ने BROA की धारा 84 और 85 और इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों जैसे *पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, शेर सिंह बनाम वित्तीय योजना आयुक्त, पंजाब, दयानंद बनाम भारत संघ* का संदर्भ लिया और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला -

> इन धाराओं की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। **<u>ये धाराएं प्रदान करती हैं कि जो कानून अविभाजित बिहार राज्य पर लागू होते थे, वे अधिनियम द्वारा बनाए गए नए राज्यों पर भी लागू होते रहेंगे। जो कानून पहले से लागू थे, वे बिहार के विभाजन और नए झारखंड राज्य के गठन के बावजूद लागू रहेंगे। ये तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें बदला, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है... धारा 84 के तहत, किसी भी ऐसे कानून (जिसमें प्रश्न में अधिसूचना भी शामिल है) के क्षेत्रीय संदर्भों को, जो बिहार राज्य पर लागू थे, नियत दिनांक से पहले बिहार राज्य के मौजूदा क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है।</u>** इन दोनों प्रावधानों के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि नियत दिनांक से पहले लागू किसी भी कानून के क्षेत्रीय संदर्भों को नियत दिनांक से पहले बिहार राज्य के मौजूदा क्षेत्रों के रूप में माना जाना चाहिए। बिहार या झारखंड राज्य के संदर्भ में उनके आवेदन की सुविधा के लिए, संबंधित सरकार उस दिनांक से दो वर्षों की समाप्ति से पहले आदेश द्वारा, कानून को निरस्त या संशोधित करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त संशोधनों और परिवर्तनों को कर सकती है। जब तक ऐसा कानून कानूनी रूप से निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता, तब तक यह प्रभावी रहेगा। इसके संशोधन या परिवर्तन के बाद, यह संशोधनों और परिवर्तनों के अधीन प्रभावी रहेगा।
>
> **(प्रभावित किया गया)**
>
> **...**

---

[15] (1996) 7 SCC 47

[16] (2004) 6 सेक 689

34. हमारे उपर्युक्त विचार-विमर्श से, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत मौजूदा राज्य का पुनर्गठन करने वाले कानून और मूल राज्य में लागू कानूनों के नए बने पुनर्गठित राज्य पर प्रभाव को लेकर सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आवश्यक होगा क्योंकि हमारे विचार में, बिहार में पुनर्गठन से पहले प्रकाशित प्रथम रजिस्टर को नए बने झारखंड का प्रथम रजिस्टर माना जाएगा, बशर्ते इसमें उन फार्मासिस्टों का नाम शामिल हो जो उन क्षेत्रों के निवासी थे जो झारखंड को स्थानांतरित किए गए थे।

35. जब एक राज्य भारतीय राष्ट्र का हिस्सा होते हुए पुनर्गठित होता है, तो कानून के संदर्भ में निम्नलिखित तीन बातें होती हैं: (i) मौजूदा राज्य (मूल राज्य) जो विभिन्न कानून बनाता है, वह अस्तित्व में रहेगा; (ii) नए राज्य का गठन कुछ क्षेत्रों को स्थानांतरित करके किया जाता है, जिसे कानूनों के लागू होने के संदर्भ में मूल राज्य के क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा; और (iii) मूल राज्य द्वारा बनाए गए कानून नए राज्य पर लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें नए राज्य के संदर्भ में सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाता है और 'कानून' जैसा कि परिभाषा खंड में परिभाषित है, वह कानून होगा जो मौजूदा राज्य में लागू था और नए बने राज्य में लागू होगा।

36. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्य को बदलने, संशोधित करने, विलीन करने, नए राज्यों का गठन करने, क्षेत्र को कम करने या बढ़ाने का अधिकार रखती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू 'स्वच्छ पट्टा' का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 3[17] के तहत पुनर्गठन के समय लागू नहीं होता। पुनर्गठित राज्य सामान्यतः नई स्थिति के रूप में नहीं शुरू होते, बल्कि वे पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी होते हैं। BROA के तहत, झारखंड बिहार से अलग किया गया और दो अलग-अलग राज्य 15.11.2000 को अस्तित्व में आए। यदि कानूनों को विभाजन के दिन समाप्त कर दिया गया होता, तो नए बने राज्य को कानूनों के बिना एक राज्य के रूप में छोड़ दिया जाता, जिससे अराजक स्थिति उत्पन्न होती। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, BROA के अनुच्छेद 84 और 85 जैसे प्रावधान बनाए गए हैं ताकि निरंतरता बनी रहे, और साथ ही राज्यों को आदेश जारी करने के माध्यम से आवश्यक परिवर्तनों और अनुकूलनों को करने का अधिकार प्राप्त हो सके और इसके बाद विधान द्वारा संशोधन किया जा सके।

37. पहले परिभाषित अनुसार 'कानून' में 'कानून की ताकत वाले अन्य उपकरण' शामिल हैं। 'शामिल' शब्द के उपयोग को देखते हुए, अनुच्छेद 2(f) के तहत 'कानून' की परिभाषा को व्यापक रूप से व्याख्यायित किया जाएगा। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम मानते हैं कि बिहार द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर BROA के अनुच्छेद 2(f) के तहत कानून की ताकत रखता है।

38. उपर्युक्त के दृष्टिगत, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बिहार सरकार द्वारा दवाइयों के रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर, धारा 30 की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया, तो यह निर्णायक है और किसी भी संशोधन को समावेश के रूप में तब तक किया जा सकता है जब तक कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शिक्षा नियमावली तैयार नहीं की जाती। इसके लिए सक्षम प्राधिकरण धारा 31 के तहत निर्धारित योग्यताओं पर विचार कर सकता है। हालांकि, शिक्षा नियमावली के लागू होने के बाद और बाद में रजिस्ट्रेशन के समय, सरकार को शिक्षा नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति शिक्षा नियमावली

17. उपर्युक्त, 13 पर

के अनुसार योग्यताओं को पूरा नहीं करता है, वह फार्मेसी रजिस्टर में प्रवेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से, जब बिहार राज्य को फिर से प्रथम रजिस्टर तैयार करने से रोका गया है, तो झारखंड राज्य को भी कानून के अनुसार प्रथम रजिस्टर फिर से तैयार करने का अधिकार नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में सही निष्कर्ष पर पहुँचा है।

39. इस समय हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से धारा 84 के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, हालांकि उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पूरे तरीके से प्रथम रजिस्टर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के लिए प्रथम रजिस्टर वही रजिस्टर है जो पूर्ववर्ती बिहार के लिए तैयार किया गया था, जिसमें सभी फार्मासिस्ट शामिल हैं जो अब झारखंड राज्य में रह रहे हो सकते हैं।

40. फैसले के पहले भाग में हमने बिहार द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर पर धारा 84 के प्रभाव पर विचार किया है। यह हमें विशेष रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था। फिर भी, जैसा कि हमने पहले देखा है, जब भी नए बने राज्य ने प्रथम रजिस्टर को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहा, ऐसे प्रावधान विशेष रूप से बनाए गए थे। हम ऐसे प्रावधानों को उद्धृत कर सकते हैं:

आंध्र प्रदेश [आंध्र ए.एल.ओ., 1954 (01.10.1953)]

33A. आंध्र राज्य के लिए फार्मासिस्टों के रजिस्टर के विशेष प्रावधान। - (1) इस अध्याय में कुछ भी वर्णित न होते हुए, ऐसा व्यक्ति जिसे आंध्र राज्य सरकार इस संबंध में अधिकृत करती है (जिसे आगे अधिकृत अधिकारी कहा जाएगा) आंध्र राज्य के लिए एक अलग फार्मासिस्ट रजिस्टर तैयार करेगा जैसा कि यहां प्रदान किया गया है और वह रजिस्टर सभी उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के तहत तैयार किए गए रजिस्टर के रूप में माना जाएगा।

महाराष्ट्र [एस.ओ. 2814, प्रकाशित गजट ऑफ इंडिया, 19.08.1964, भाग II, एस. 3(ii), एक्स्ट., पृ. 717 (722, 723)]

29A. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए फार्मासिस्टों के रजिस्टर के संबंध में प्रावधान। - (1) जैसे ही बॉम्बे राज्य फार्मेसी काउंसिल (पुनर्गठन) आदेश, 1964, जो इंटर-स्टेट कॉर्पोरेशन एक्ट, 1957 के तहत धारा 4 के तहत बनाया गया, प्रभावी होता है, महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी काउंसिल, धारा 30, 31 और 32 में वर्णित किसी भी चीज के बावजूद, महाराष्ट्र राज्य के लिए फार्मासिस्टों का रजिस्टर तैयार और बनाए रखेगी। रजिस्टर में शामिल किया जाएगा:-

(a) सभी फार्मासिस्ट जो पूर्व बॉम्बे राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर में शामिल हैं जो धारा 29 के तहत उचित रूप से तैयार और बनाए रखे गए थे, जिनके आवासीय पते जो उक्त तिथि पर दिखाई देते हैं, गुजरात राज्य के क्षेत्रों या पूर्व बॉम्बे राज्य के उस क्षेत्र में नहीं आते जो 1 नवम्बर, 1956 को कर्नाटका या राजस्थान में स्थानांतरित कर दिए गए थे, और पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के रजिस्टर में भी जिनके आवासीय पते उक्त तिथि पर दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रों में आते हैं:

प्रस्तावना: पूर्व मध्य प्रदेश राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर में शामिल नाम महाराष्ट्र राज्य के रजिस्टर में शामिल नहीं किए जाएंगे जब तक कि महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी काउंसिल विदर्भ क्षेत्र में धारा 19-ए की उपधारा (5) के खंड (2) के तहत कार्यशील और संचालन में न आ जाए।

41. जहाँ तक BROA की बात है, हालांकि अधिनियम को BROA की धारा 84 और 85 के तहत अपनाया गया था, कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से, धारा 84 को लागू करते हुए, हम यह मानते हैं कि पूर्ववर्ती बिहार द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर झारखंड के लिए प्रथम रजिस्टर माना जाएगा और ऐसा ही रहेगा। हालांकि, यह झारखंड को धारा 32, 32A और 32B के अनुसार बाद के रजिस्ट्रेशन को करने से नहीं रोकता है। ऐसी स्थिति में, झारखंड का संबंधित प्राधिकरण फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर संशोधित शिक्षा नियमावली का पालन करना होगा।

42. BROA की धारा 86 इस न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह अधिकार देती है कि वह कानून की व्याख्या इस प्रकार करे कि धारा 84 और 85 को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। BROA की सभी प्रावधानों पर विचार करने के बाद, हमारा मत है कि बिहार के पूर्ववर्ती राज्य के प्रथम रजिस्टर में जिन फार्मासिस्टों का आवासीय पता झारखंड राज्य की सीमा में आता है, उन्हें झारखंड के प्रथम रजिस्टर का हिस्सा माना जाएगा। रजिस्टर में भविष्य में अतिरिक्त नामों को केवल फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार शामिल किया जाएगा। हम यह भी आशा करते हैं कि झारखंड राज्य निकट भविष्य में, यदि पहले से नहीं किया गया है, तो एक राज्य परिषद का गठन करेगा। परिणामस्वरूप, झारखंड राज्य सरकार की 12.11.2001 की अधिसूचना को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश और धारा 30 के अनुसार रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के गठन और धारा 31 के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने की विज्ञप्ति को सही ठहराया जाता है।

43. उपर्युक्त विश्लेषण और चर्चा के आलोक में, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:

a) पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार किया गया प्रथम रजिस्टर झारखंड और बिहार के नए बने राज्य के लिए प्रथम रजिस्टर के रूप में माना जाएगा।

b) पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर को फार्मासिस्टों द्वारा पंजीकरण के समय प्रदान किए गए आवासीय पते के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

c) झारखंड राज्य को राज्य परिषद का गठन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता है।

d) वे फार्मासिस्ट जिनका नाम पूर्ववर्ती बिहार राज्य के प्रथम रजिस्टर में दर्ज है, और जो केंद्रीय फार्मेसी काउंसिल द्वारा बनाए गए शिक्षा नियमावली के लागू होने से पहले पंजीकृत हुए हैं, और जो उस राज्य में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते जहां उनका आवासीय पता आता है, वे फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार दूसरे राज्य में पंजीकरण करा सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन फार्मासिस्टों के नाम पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तैयार किए गए प्रथम रजिस्टर में थे, उन्हें झारखंड राज्य में धारा 32(2) के तहत औपचारिक रूप से पंजीकरण प्राप्त करना होगा और उन्हें शिक्षा नियमावली द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

रंजन सिन्हा और एएनआर. बनाम अजय कुमार विश्वकर्मा

उदाहरण नं. 1 - यदि 'A' का नाम पूर्ववर्ती बिहार राज्य के प्रथम रजिस्टर में दर्ज है। वह फार्मेसी अधिनियम की धारा 32 (2) के अनुसार झारखंड राज्य में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, 'A' को शिक्षा नियमावली के तहत निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

44. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपील समाप्त की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुज्जरल अपील समाप्त की गई।

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**